ए-45011/4/2023-समन्वय.II

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

***

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2023

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को इस पत्र के साथ अगस्त, 2023 के महीने में आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के मासिक सारांश के अगोपनीय भाग परिचालित करने का निर्देश दिया गया है।

सु. सामंत

(सुश्रुत सामंत)

उप सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं. 2309- 5244

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. मंत्रिमडल सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
4. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।
6. प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव, पीएमओ, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
7. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली।
8. नीति आयोग के सभी सदस्य, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
10. राज्य मंत्री (वित्त) के निजी सचिव, वित्त सचिव के प्रधान निजी सचिव, सचिव (ईए) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (व्यय) के प्रधान निजी सचिव, सचिव (दीपम) के प्रधान निजी सचिव ।
11. श्री वी. अनंत नागेश्वरन, मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
12. अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
13. श्री मनोज सहाय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
14. सुश्री अपर्णा भाटिया, सलाहकार (प्रशासन/समन्वय/सी एवं सी)
15. सुश्री मनीषा सिन्हा, अपर सचिव (जी20 लॉजिस्टिक्स (समन्वय-II)/ओएमआई/क्रिप्टो आस्ति और सीबीडीसी)
16. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागों के प्रमुख।
    संयुक्त सचिव (आईपीपी/ संयुक्त सचिव (आईएसडी)/ संयुक्त सचिव (अन्वे.)/ संयुक्त सचिव (बजट) जेएस (एफएम) /सभी सलाहकार/सीएएए

17. श्री राजेश मल्होत्रा, महानिदेशक (एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

18. गार्ड फ़ाइल - 2023।

ए-45011/4/2023-समन्वय.II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
***

विषय: अगस्त, **2023** के महीने में आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का मासिक सारांश।

1. महीने के दौरान लिए गए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय और प्रमुख उपलब्धियां:

वृहत आर्थिक अवलोकन:

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के अनुमानों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद वास्तविक रूप से 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा। उपभोग और निवेश की बेहतर घरेलू मांग ने इस तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि को गति दी। शहरी बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट ने भी अर्थव्यवस्था के लिए निजी खपत की वृद्धि बनाए रखने में योगदान दिया है। उपभोग में बढ़ोतरी के कारण वस्तुओं और सेवाओं की मांग में वृद्धि हुई, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में अधिक उत्पादन और मूल्य वर्धित वृद्धि देखी गई। पूंजीगत व्यय पर सरकार द्वारा निरंतर जोर देने से घरेलू निवेश को भी मजबूती मिली। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए उपायों ने राज्यों को भी अपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है। बाहरी मांग घरेलू विकास को प्रोत्साहित करने में और अधिक सहायक रहा है। सेवा निर्यात के शानदार प्रदर्शन से वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में निवल निर्यात का योगदान बढ़ गया है। जुलाई/अगस्त 2023 में उच्च-आवृत्ति संकेतक वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में विकास की गति जारी रहने का संकेत देते हैं।

बैंकिंग क्षेत्र में भी बेहतर प्रदर्शन देखा गया है। विभिन्न संकेतकों से पता चलता है कि मार्च 2023 तक गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) में गिरावट, पूंजी एवं जोखिम-भारित आस्ति के अनुपात (सीआरएआर) में सुधार, आस्तियों से अधिक प्रतिफल (आरओए) और इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) के माध्यम से इस क्षेत्र की समुत्थानशीलता बढ़ रही है। इसी तरह, मार्च 2023 तक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) के आंकड़ों ने उनकी लाभप्रदता और जोखिम उठाने की प्रवृत्ति में सुधार का संकेत दिया। आरबीआई द्वारा जुलाई 2023 के अनुमानों के अनुसार, अप्रैल 2022 से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के गैर-खाद्य बैंक ऋण में लगातार और व्यापक आधार पर वृद्धि हुई है।

बैंकिंग प्रणाली की अच्छी स्थिति का श्रेय पिछले दशक में कारपोरेट क्षेत्र द्वारा शुरू की गई ऋण शोधन प्रक्रिया को दिया जा सकता है। महामारी के वर्षों के दौरान, इस क्षेत्र की

आय में गिरावट के परिणामस्वरूप फिर से ऋण का स्तर बढ़ गया। प्रतिबंधों में ढील और नियमित आर्थिक सुधार के साथ, कारपोरेट तुलन-पत्र में क्रमिक सुधार और मजबूती देखी गई है। निजी गैर-वित्तीय क्षेत्र एवं मुख्य ऋण अनुपात में गिरावट आई है और विभिन्न उत्तोलन अनुपातों में सुधार हुआ है। तुलन-पत्र के पुनर्गठन ने कंपनियों को निवेश गतिविधियों का विस्तार करने और आर्थिक झटकों के प्रति अधिक समुत्थानशीलता बनने के लिए एक मजबूत स्थिति में रखा है।

वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में मजबूत आर्थिक वृद्धि के पूरक के रूप में, संगठित क्षेत्र के रोजगार ने भी बेहतर विकास का संकेत दिया, जिसमें ईपीएफओ में शामिल होने वाले नए सदस्यों में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलने के बजाय अधिक सदस्य फिर से जुड़ना शामिल है।

कोर मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति सहित खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में घटी है। कई महत्वपूर्ण आदानों के शुल्कों में समायोजन सहित सरकार द्वारा किए गए उपायों ने मुख्य मुद्रास्फीति को 40 महीने के निचले स्तर पर लाने में मदद की। बफर स्टॉक बनाने, उत्पादक केंद्रों से समय पर खरीद और सब्सिडी वाले वितरण सहित विशिष्ट फसलों के लिए लक्षित उपायों से सरकार के हस्तक्षेप के कारण अगस्त में उपभोक्ता खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति घटकर 9.9 प्रतिशत हो गई।

आने वाले समय में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें मुद्रास्फीति के आंकड़ों में परिलक्षित होंगी। अगस्त में मानसून की कमी खरीफ और रबी दोनों फसलों को प्रभावित कर सकती है। वैश्विक शेयर बाजार में गिरावट के मद्देनजर शेयर बाजार में सुधार हमेशा मौजूद रहने वाला जोखिम होता है। कारपोरेट लाभप्रदता के उज्ज्वल बिंदु, जैसे निजी क्षेत्र में पूंजी निर्माण, बैंक ऋण वृद्धि और निर्माण क्षेत्र में गतिविधि, इन जोखिमों को दूर करते हैं।

2. महत्वपूर्ण घटनाक्रम:

(i) माननीय वित्त मंत्री ने माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के साथ 19 अगस्त, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में **जी-20 संयुक्त वित्त और स्वास्थ्य ट्रैक मंत्रिस्तरीय बैठक की सह-अध्यक्षता** की।

(ii) **निम्नलिखित महत्वपूर्ण बैठकों में माननीय वित्त मंत्री ने भाग लिया:**

क) 03 अगस्त, 2023 को माननीय वित्त मंत्री और विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक समूह के बीच एक बैठक आयोजित की गई।

ख) माननीय वित्त मंत्री ने 19 अगस्त, 2023 को आईएफएससी-गिफ्ट सिटी में चल रही विभिन्न पहलों की समीक्षा की। समीक्षा में वित्त मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य और नियामकों के सचिवों ने भाग लिया।

ग) माननीय वित्त मंत्री ने वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालयों के लिए चिंतन शिविर की अध्यक्षता की, जो 20 से 22 अगस्त, 2023 तक केवडिया, गुजरात में आयोजित किया गया था। दोनों राज्य मंत्रियों (वित्त) ने भी सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। चिंतन शिविर में लगभग 100 अधिकारियों (संयुक्त सचिव और उससे ऊपर) ने भाग लिया, जिसमें छह विभागों के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार, सीबीडीटी और सीबीआईसी के अध्यक्ष, लेखा महानियंत्रक आदि शामिल थे।

(iii) आधिकारिक स्तर पर निम्नलिखित **महत्वपूर्ण बैठकें** आयोजित की गईं/भाग लिया गया:

क) जी-20 दिल्ली घोषणा पत्र के लिए जी-20 वित्त ट्रैक पैराग्राफ का मसौदा तैयार करने का सत्र 27 से 28 अगस्त, 2023 तक वर्चुअल तरीके से आयोजित किया गया।

ख) आईएमएफ-एफएसबी सिंथेसिस पेपर: क्रिप्टो-एसेट्स के लिए नीतियां, सीसीपी वित्तीय संसाधन और एनबीएफसी लीवरेज पर रिपोर्ट के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एफएसबी की पूर्ण बैठक 29 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई।

ग) एआईआईबी के निदेशक मंडल ने तिमाही वित्तीय विवरणों पर चर्चा करने के लिए एआरसी सदस्यों के परामर्श से वित्तीय विवरणों पर विचार करने के लिए 15 अगस्त, 2023 को वर्चुअल बैठक की।

घ) एआईआईबी के निदेशक मंडल ने वित्त पोषण पर एआईआईबी की परिचालन नीति, उभरते बाजार अवसंरचना कोष, हरित विकास परियोजना और जलवायु परिवर्तन कोष पर विचार करने के लिए 23 अगस्त, 2023 को वर्चुअल बैठक की।

ङ) एआईआईबी के निदेशक मंडल ने एआईआईबी के कार्य का समर्थन करने के लिए निवेश परियोजनाओं, जून रिट्रीट फॉलो-अप और बाहरी विशेषज्ञता पर विचार करने के लिए 30 अगस्त, 2023 को वर्चुअल बैठक की।

च) बहुपक्षीय विकास बैंकों/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तपोषण प्राप्त करने के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग स्क्रीनिंग कमेटी की 142वीं बैठक 31 अगस्त, 2023 को आयोजित की गई।

छ) 10 अगस्त, 2023 को चुनिंदा राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए वर्चुअल त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया।

ज) भारत-ब्रिटेन वार्ता (राउंड 9) 17-18 अगस्त, 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई।

झ) ईपीटीए के तहत निवेश अध्याय पर भारत-कनाडा वार्ता 18 अगस्त, 2023 को वर्चुअल रूप से आयोजित की गई।

ञ) भारत-ऑस्ट्रेलिया निवेश समझौता वार्ता (राउंड 7) 14 और 16-18 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

ट) एफएसडीसी उप-समिति की 30वीं बैठक 28 अगस्त, 2023 को आरबीआई के गवर्नर की अध्यक्षता में आरबीआई, मुंबई में आयोजित की गई।

ठ) सेबी के तहत 50+ विनियमित संस्थाओं के बोर्ड स्तर के अधिकारियों के लिए पहला साइबर सुरक्षा टेबल टॉप अभ्यास, 31 अगस्त, 2023 को आयोजित किया गया। सीईआरटी-इन और सेबी के बीच एक संयुक्त पहल, अभ्यास इस क्षेत्र की साइबर सुरक्षा परिपक्वता को बढ़ाने और साइबर सुरक्षा जागरूकता पैदा करने के लिए अभिन्न चुनौतियों और अवसरों का व्यवस्थित रूप से आकलन करने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया।

(iv) इस महीने के दौरान **निम्नलिखित अधिसूचना जारी की गई :**

(क) इक्विटी और संबंधित लिखतों के मोचन पर प्राप्त आय का निवेश करने के लिए गैर-सरकारी भविष्य निधि के लिए निवेश दिशानिर्देशों में संशोधन।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आईडीएफ-एनबीएफसी के लिए दिशा-निर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि आईडीएफ-एनबीएफसी अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण में अधिक भूमिका निभा सकें और एनबीएफसी द्वारा अवसंरचना क्षेत्र के वित्तपोषण को नियंत्रित करने वाले विनियमों में सामंजस्य स्थापित कर सकें।

(vi) गुयाना में चेद्दी जगन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सौर फोटो वोल्टाइक पावर प्लांट की स्थापना के लिए 08 अगस्त, 2023 को गुयाना सरकार को 2.50 मिलियन अमरीकी डालर की भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) की पेशकश के लिए माननीय वित्त मंत्री की मंजूरी से अवगत कराया गया।

(vii) मंगोलिया सरकार को 1,000 मिलियन अमरीकी डालर की लाइन ऑफ क्रेडिट का समयपूर्व समापन करने के लिए माननीय वित्त मंत्री की मंजूरी और तीन नई एलओसी अर्थात 203.34 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए एलओसी -1, 599 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए एलओसी -2 और 190 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के लिए एलओसी -3 की मंजूरी से 15 अगस्त, 2023 को मंगोलिया सरकार को अवगत कराया गया।

(viii) बहुपक्षीय विकास एजेंसी के साथ निम्नलिखित ऋण/अनुदान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए:

क) "रिनिमेन्ट केरल डिवलपमेंट प्रोग्राम" के लिए 150 मिलियन अमरीकी डालर के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक के साथ ऋण पर हस्ताक्षर किए गए।

(ix) इस महीने के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में निम्नलिखित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए:

(क) आईआईएम बैंगलोर में 31 जुलाई से 04 अगस्त, 2023 तक 'पूंजी संरचना निर्णय और परियोजना वित्त' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ख) आईआईएम कलकत्ता में 7 से 11 अगस्त, 2023 तक 'परियोजना प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ग) आईआईएम इंदौर में 7 से 11 अगस्त, 2023 तक 'पीपीपी परियोजना वित्त, जोखिम और मूल्यांकन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(घ) आईआईएम रायपुर में 28 अगस्त से 01 सितंबर, 2023 तक 'परियोजना व्यवहार्यता और परियोजना वित्तपोषण तथा निष्पादन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(ङ) 21 से 25 अगस्त, 2023 तक एजेएनआईएफएम में 'सार्वजनिक निजी भागीदारी- एक बुनियादी परिप्रेक्ष्य' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

3. न्यूनतम शासन, अधिकतम सुशासन

सूचना प्रस्तुत करने में आईसीटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

4. एसीसी निर्देशों/आदेशों का अनुपालन न करना: शून्य

5. माह के दौरान मंजूर किए गए एफडीआई प्रस्तावों का ब्यौरा और विभाग में अनुमोदन की प्रतीक्षा में एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति:

स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	:	शून्य
विभाग में अनुमोदनार्थ प्रतीक्षा हेतु	:	15